

# मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए योग का सहारा

-वीणा भाटिया

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बहुप्रचारित कार्यक्रम संपन्न हो गया। नई दिल्ली में राजपथ पर हजारों लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने योग किया और राजपथ को योगपथ घोषित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने भी योग किया। कहा गया कि पहली बार दुनिया के सैंकड़ों देशों में लोगों ने योग किया और इससे योग को विश्व में मान्यता मिल गई। नरेन्द्र मोदी की सरकार इसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित कर रही है, पर इसके साथ ही इस कार्यक्रम का विरोध भी कम नहीं हुआ। भाजपा विरोधी तमाम दलों ने सरकारी खर्च पर ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने को एक ढकोसला बताया है और कहा है कि इसके माध्यम से मोदी सरकार मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम को लेकर मोदी की काफ़ी आलोचना हो रही है। इसे बेमतलब का बताया गया है। कहा जा रहा है कि इसका मकसद देश के योग कारोबारियों को मदद पहुंचाना है, जिनमें बाबा रामदेव की प्रधानमंत्री मोदी और भगवा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नजदीकी छिपी नहीं है। इस कार्यक्रम के दौरान हुई कई बातों का काफ़ी मजाक भी उड़ाया जा रहा है। योग कार्यक्रम के लिये चीन से चटाइयां मंगाई गईं, जबकि मोदी 'मेक इन इंडिया' की बात करते हैं। क्या देश इस लायक भी नहीं कि स्वयं चटाइयां उपलब्ध करा सके। इसके अलावा, यह भी कहा जा रहा है कि मोदी ने योग करने के दौरान आसनों में चूक भी की इनके द्वारा तिरंगे को गले में लपेटने, पैरों के पास रखने और उससे मुंह पोछने को लेकर भी उन पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा था कि क्या मोदी स्वयं योग करते हैं। इसे एक कटाक्ष माना गया। बहरहाल, इतना तो तय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अभूतपूर्व स्तर पर प्रचार-प्रसार किया गया। ऐसा लगा कि सरकार यह मान कर चल रही है कि योग से ही जनता की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जाहिर है, ऐसे में सरकार की नीयत पर सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि एक साल का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी मोदी सरकार जनता से किए वायदों में से एक भी पूरा नहीं कर सकी है और ऐसा करने की उसकी मंशा भी नहीं दिख रही। सरकार

**उल्लेखनीय है कि सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सफ़ाई-स्वच्छता को सबसे बड़े मुद्दे के रूप में उभारा। स्वच्छता बहुत ही अच्छी बात है और इसकी जरूरत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रचारवादी तरीके से इसे चलाया, उसमें यह कुल मिलाकर एक तमाशा बन कर रह गया। उन्होंने सफ़ाई करने के लिए सेलिब्रिटीज को नामांकित करना शुरू किया और बड़े-बड़े सेलिब्रिटी हाथों में झाड़ू उठाकर फ़ोटो खिंचाने लगे। मंत्री से लेकर आला अफ़सर तक इस अभियान में शामिल हो गए। नेताओं और मंत्रियों में सफ़ाई करते हुए फ़ोटो खिंचवा कर अखबारों में छपने के लिए एक होड़-सी शुरू हो गई। कुछ मामले तो ऐसे सामने आए जिनमें सड़क पर पहले कचरा फ़ेलाया गया और इसके बाद नेता जी ने आकर झाड़ू चलाते हुए फ़ोटो खिंचवाई। इससे मोदी जी और उनकी सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई। यह समझना मुश्किल नहीं कि गंदगी और अस्वच्छता का मूल कारण गरीबी और लोगों के पास साधनों की कमी के साथ सरकारी व्यवस्था का निकम्मापन भी है। बहरहाल, कुछ ही दिनों में मोदी जी के स्वच्छता अभियान की पोल-पट्टी खुल गई। यह महज एक तमाशा ही साबित हुआ।**

का पूरा ध्यान प्रचार पर लगा है। चुनाव पूर्व प्रचार तो समझ में आता है, पर बहुमत से सरकार बना लेने के बाद भी सरकार प्रचार के सहारे ही टिकी रहना चाहती हो, तो यह एक सोचने वाली बात है।

उल्लेखनीय है कि सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सफ़ाई-स्वच्छता को सबसे बड़े मुद्दे के रूप में उभारा। स्वच्छता बहुत ही अच्छी बात है और इसकी जरूरत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रचारवादी तरीके से इसे चलाया, उसमें यह कुल मिलाकर एक तमाशा बन कर रह गया। उन्होंने सफ़ाई करने के लिए सेलिब्रिटीज को नामांकित करना शुरू किया और बड़े-बड़े सेलिब्रिटी हाथों में झाड़ू उठाकर फ़ोटो खिंचाने लगे। मंत्री से लेकर आला अफ़सर तक इस अभियान में शामिल हो गए। नेताओं और मंत्रियों में सफ़ाई करते हुए फ़ोटो खिंचवा कर अखबारों में छपने के लिए एक होड़-सी शुरू हो गई। कुछ मामले तो ऐसे सामने आए जिनमें सड़क पर पहले कचरा फ़ेलाया गया और इसके बाद नेता जी ने आकर झाड़ू चलाते हुए फ़ोटो खिंचवाई। इससे मोदी जी और उनकी सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई। यह समझना मुश्किल नहीं कि गंदगी और अस्वच्छता का मूल कारण गरीबी और लोगों के पास साधनों की कमी के साथ सरकारी व्यवस्था का निकम्मापन भी है। बहरहाल, कुछ ही दिनों में मोदी जी के स्वच्छता अभियान की पोल-पट्टी खुल गई। यह महज एक तमाशा ही साबित हुआ।

योग को लेकर सरकार ने जैसा उत्साह दिखाया और न जाने कितने करोड़ खर्च,

उसका परिणाम क्या होगा, यह विचारणीय है। योग को सरकार कुछ इस तरह प्रचारित कर रही है मानो सारी समस्याओं का निदान इसी से संभव है। इसे सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। साथ ही, संघ परिवार ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होनेवालों पर देशद्रोही होने तक का आरोप लगाने लगता है। संघ परिवार के कई संगठन अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ अनुचित बयानबाजी करने लगते हैं। भूलना नहीं होगा कि मोदी सरकार की लोकप्रियता सालभर के भीतर ही बहुत तेज़ी से घटी है। महंगाई कम करना, काला धन वापस लाना, भ्रष्टाचार दूर करना, शासन व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करना आदि मोदी जी के वो वायदे थे, उनमें एक भी पूरा करने की तरफ़ सरकार ने कदम नहीं उठाया है। सरकार बनने के बाद से ही महंगाई में बेतहाशा वृद्धि जारी है। कालाधन वापस लाने का मुद्दा गुम हो गया। लेकिन मोदी के शासन संभालने के शुरुआती महीनों में ही संघ परिवार के नेताओं ने भारत में हिंदू राज की स्थापना की घोषणाएं करनी शुरू कर दी। लव जिहाद, घर वापसी, धर्म परिवर्तन और ऐसे-ऐसे मुद्दे उभारे जाने लगे जिनसे आम जनता का भला क्या होता, उल्टे अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना गहराने लगी। आम चुनाव होने के पहले और मोदी सरकार बनने के बाद भी दंगे होते ही रहे, अभी भी छिटपुट हो रहे हैं। साथ ही, संतों और साधुओं के मुंह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ विषबुझे बाणों का निकलना कम नहीं हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सांप्रदायिक ताकतों को

बढ़ावा मिला है और वे बेलगाम हो गए हैं। दूसरी तरफ़, सरकार के घोषित एजेंडे में से एक भी लागू नहीं हो सका। जहां तक भ्रष्टाचार पर रोकथाम की बात है, तो ललित मोदी का मुद्दा अब सरकार के गले की फ़ांस बनता जा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ ही राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के इस मामले में बुरी तरह फ़ंसे होने के कारण मोदी सरकार की कोई साख़ नहीं रह गई है, क्योंकि सरकार ने इनके बचाव का निर्णय लिया। भ्रष्टाचार के प्रति मोदीजी के रुख को इस बात से समझा जा सकता है कि जिन येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के आरोप में कर्नाटक का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था और इससे नाराज होकर उन्होंने भाजपा से इस्तीफ़ा दे दिया था, उन्हें फिर से भाजपा में लाया गया और आज वे पार्टी के उपाध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे न जाने कितने भ्रष्ट नेता भाजपा संगठन और मोदी सरकार में शामिल हैं। आम जनता ज्यादा समय तक छलावे में नहीं रह सकती।

जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा योग को मान्यता दिए जाने का सवाल है, तो इसमें कोई विशेष गौरव वाली बात नहीं है। योग एक प्राचीन भारतीय विद्या है और संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर की प्राचीन विद्याओं, कलाओं एवं स्थलों का संरक्षण करता ही है। लेकिन इसे इस रूप में समझना कि योग से स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, बहुत बड़ा भ्रम होगा। प्राचीन भारत में योग का महत्व एक दर्शन के रूप में रहा है। लेकिन बाबा रामदेव ने योग को एक व्यायाम प्रणाली बना दिया है, जबकि यह एक विचार और चिंतन प्रणाली रहा है। प्राचीन और मध्यकालीन

भारत में कहीं यह उल्लेख नहीं मिलता कि आम जनता योग किया करती थी या उसे ऐसा करने के लिए राज्य प्रोत्साहित करता था। अगर योग चिकित्सा प्रणाली होती तो फिर आयुर्वेद का विकास क्यों होता, यह एक विचारणीय प्रश्न है। भूलना नहीं होगा कि भारत में आयुर्वेद का बहुत ही ऊंचे स्तर पर विकास हो गया था। जब यूरोप में हज़ाम सर्जन हुआ करते थे, तब आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा के लिए निष्पेतक की खोज कर ली गई थी। योग का महामामंडन करने के साथ इस एतिहासिक तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। योग को हमेशा ही एक दर्शन के रूप में देखा गया और आधुनिक विद्वानों ने भी इसे इसी रूप में स्वीकार किया है। प्राचीन काल में सिर्फ़ ऋषि-महर्षि योग साधना करते थे, गृहस्थों द्वारा योग करने का कहीं उल्लेख नहीं मिलता।

बहरहाल, आज योग का अकूत दौलत कमाने का एक जरिया बना लिया गया है। बाबा रामदेव तो अभी हाल में आए हैं। इनसे पहले महेश योगी ने विदेशों में अपने योग का जबरदस्त सिक्का जमाया और बेशुमार दौलत कमाई। वैसे, इस देश में योग के छोटे-बड़े कई केन्द्र रहे हैं, जहां मुख्य तौर पर पश्चिमी देशों से लोग आकर योग साधना में शांति की तलाश करते रहे। आज योग का पूरी तरह व्यवसायीकरण हो चुका है। बाबा रामदेव ने तो इसे उद्योग बना डाला है। लेकिन बड़े से लेकर छोटे शहरों तक में भी योग की दुकानें खुल चुकी हैं, जहां लोगों को भ्रमित कर उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। हरिद्वार के योग प्रशिक्षण केन्द्रों से अनेक विदेशी युवक-युवतियां चार-छः महीने योग का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने देशों में योग प्रशिक्षण केन्द्र खोल लेते हैं और कमाई करते हैं। विक्रम चौधरी नाम का एक ऐसा योगाचार्य है जो अमेरिका में 'हठ योगा' सिखाता है। कई पश्चिमी देशों में उसके प्रशिक्षण केन्द्र हैं। उस पर अपनी शिष्याओं के यौन शोषण और बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी स्वच्छता तो कभी योग के जरिए वे जनता में विश्वास कायम नहीं कर सकते। इसके लिए तो जनता के मूल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पर जनता की मूल समस्याओं को हल कर पाना इस सरकार के वश में नहीं, न ही वह उसके एजेंडे में है। ऐसे में, कल स्वच्छता अभियान, आज योग तो आने वाले दिनों में ऐसे ही मुद्दों को खड़ा कर सरकार जनता का ध्यान भटकाएगी।

## आसार अच्छे दिनों के.....

अच्छे दिन आनेवाले हैं, आयेगे अच्छे दिन! आना भी चाहिए। लेकिन कैसे? किसके भरोसे? किस रास्ते? जो सुसंस्कृत, श्रम साधक नागरिक के प्रयास से माटी पुत्रों के भरोसे, मानवता के रास्ते ही अच्छे दिन आते हैं। संकेतों पर विश्वास हो रहा है तो आयेगे ही अच्छे दिन। इस कामना और विश्वास से स्पष्ट होता है विगत अच्छे दिन नहीं थे। आज़ादी के मस्ती के साथ ही अच्छे दिनों की कल्पनाओं, संभावनाओं, योजनाओं में भटकते रहे हैं। बेरे बन-बनकर ही अच्छे परिणाम की आशा में भटकते रहे हैं। चलिए अब तो अधिसंख्यक मतदाता अच्छे दिनों को मनवांछित युगगाथा में पिरोने में तत्पर हैं तो अवश्य लाये जायेंगे।

इस समय भारत भूमि पर उपस्थित लोगों को दो अतुलनीय उपलब्धियों का लाभ है। एक 67 सालों के बुरे दिनों को झेल जाने (विजयी होने) का गौरव तथा अच्छे दिनों का सुख भोग। अब अच्छे और बुरे तो समझ है। एक जहां है, दूसरे की उपस्थिति अनिवार्य है। कहीं तो दोनों अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। सरकारी जीवन के बुरे दिन, व्यंग्यकारी, असरकारी के लिए अच्छे होते हैं। चोर लुटेरों, असामाजिक तत्वों, कायर कपटियों, हरामखोरों के अच्छे दिन, ईमानदारों,

**इस समय भारत भूमि पर उपस्थित लोगों को दो अतुलनीय उपलब्धियों का लाभ है। एक 67 सालों के बुरे दिनों को झेल जाने (विजयी होने) का गौरव तथा अच्छे दिनों का सुख भोग। अब अच्छे और बुरे तो समझ है। एक जहां है, दूसरे की उपस्थिति अनिवार्य है। कहीं तो दोनों अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है।**

श्रमशीलों, सभ्यशीलों के बुरे दिन ही होंगे। इनके अच्छे दिन तो उनके बुरे। हर व्यक्ति समूह का गिरोह (प्रतिष्ठान) आदि अपने लिये सकारात्मक और सफलता भरे खुशहाली के अच्छे दिन मानता है। सबको जीने का अधिकार है। कई लोग तो दूसरों को पीड़ित और मारकर अच्छे दिन लाते हैं। भारत में भले लोगों की अधिकता मानकर चलें तो साठ साल पहले और अधिक लोग भले रहे होंगे। जिनमें से कुछ लोग अपने लिए अच्छे दिन की तलाश में बुरे बन गये।

अब तो सरकारी जीवन में वफ़ादारी, समझदारी, सेवाहारी, आज्ञाकारी, फल-तरकारी सबके लिए आरी-पारी के दिन

आने वाले हैं। सृष्टि में परंपराएं, व्यवस्थाएं, स्वभाव, आचरण, वेदना, रिश्ते आदि सभी तो परिवर्तनीय हैं तो बुरे का जुड़वां भाई अच्छे की बारी क्यों नहीं? समय बलवान है। नैसर्गिक, शक्तियां, निश्चित सनातन प्रक्रिया के तहत विचार भावना और आचरण को प्रभावित करते हैं। आपके विचार अथवा भावना में अच्छे दिनों की सम्भावना है तो यथा सम्भव अच्छा आदमी बनें। अपने कुकर्मों/अपराधों की सज़ा स्वयं मांगें। या फिर स्वयं को दंडित करें। ऐसा नहीं करने वालों को भारतभूमि से निष्कासित करें या जीवित दफन करें। जो भी आड़े आता है कानून, संविधान या कुछ और तो उन्हीं भी दफन करें। अधिकांश बुरी स्थितियां संविधान और कानून से पनपी हैं। राजनीतिक बुरे कर्मों का व्यावहारिक शस्त्र यही है।

जबान से मुकरने वाला इंसान नहीं रह जाता। दूसरों का शोषक परजीवी कीट होता है। सामयिक निर्वाह से अधिक खर्च (शान, दबदबा, स्वार्थवश) करने वाला, समाज का आर्थिक अपराधी होता है। करीब से देखें तो गरीबी रेखा के बजाय अमीरी की रेखा की जरूरत है। पर यह किसके समझ में आता है। इसे समझे बिना अच्छे दिन की कल्पना निरर्थक है।

-नागरिक

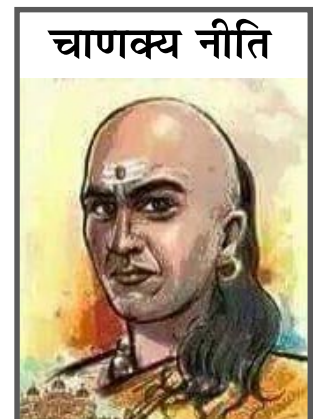


**मैं गुजराती हूं  
मेरे खून में व्यापार है**

- प्रधानमंत्री

**जहां का राजा व्यापारी  
वहां की प्रजा भिखारी**

-चाणक्य



**काश चाणक्य का कहा गलत हो जाये, लेकिन कैसे हो जायेगा अब तक तो हुआ नहीं.....**